हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्षः 11 अंकः 150 लखनऊ, गुरुवार 22 जनवरी 2026 पृष्ठः 04 मूल्यः 01 रूपये

संक्षिप्त समाचार

77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत की स्वदेशी ताकत, देश में बनी लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी

एजेंसी

नयी दिल्ली। गणतंत्र दिवस समारोह में सेना की 1721 फील्ड बैटरी (सेरेमोनियल) राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की पारंपरिक सलामी देगी। समारोह के दौरान यह आर्टिलरी बैटरी देश में ही बनी 105 मिमी लाइट फील्ड तोपों से फायरिंग कर सलामी देगी। गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी देना एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक परंपरा है। यह कर्तव्य पथ के लॉन से राष्ट्रीय ध्वज को दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। इन तोपों की फायरिंग एक साथ होने वाली तीन गतिविधियों का तालमेल होती है जिसमें प्रोटोकॉल अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराना, सेना बैंड द्वारा राष्ट्रगान बजाना और राष्ट्रपति बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रीय सलामी देना शामिल है। यह सेरेमोनियल बैटरी दिल्ली में तैनात है और इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय महत्व के अलग–अलग अवसरों पर पारंपरिक फायरिंग कर सलामी देना है। इनमें कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस, राजघाट पर शहीद दिवस, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्राध्यक्षों के दौरे शामिल हैं। यह बैटरी 172 फील्ड रेजिमेंट का हिस्सा है जो मुख्यालय 36 आर्टिलरी ब्रिगेड के तहत आती है। सेरेमोनियल बैटरी 21 तोपों की सलामी देने के लिए 105 मिमी लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल करेगी जो स्वदेशी तोप प्रणाली है। पहले यह फायरिंग ब्रिटिश काल की 25 पाउंडर तोप से की जाती थी।

लोकतंत्र की आत्मा हैं न्याय, समता व बंधुता : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को किया संबोधित

'सीखो और सिखाओ' के मंच हैं ऐसे सम्मेलनः सीएम योगी

ज्वलंत मुद्दों पर लगातार चर्चा–परिचर्चा चलाती है यूपी विधानसभा–परिषदः मुख्यमंत्री

UTTAR PRADESH
21 JANUARY, 2026
CONFERENCE

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में बुधवार को तीन दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश आए सभी अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि विधायिका लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है। संविधान संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश में न केवल विधायी कार्यों के लिए रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि यह समग्र विकास की कार्ययोजना का मंच भी होती है। संविधान के तीन शब्द (न्याय, समता और बंधुता) भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय कैसे प्राप्त होना है, इसका कानून विधायिका के मंच पर तैयार होता है। समतामूलक समाज की स्थापना में सरकार की योजनाएं योगदान दे सकें, उसकी कार्ययोजना का स्थल भी विधायिका का मंच बनता है। विधायिका बंधुता का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहां सहमति व असहमति के बीच भी संवाद के माध्यम से समन्वय होता है।

लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था देश में अत्यंत मजबूत

सीएम योगी ने कहा कि देश में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है और यह दुनिया के लिए प्रेरणा है। सदन में जनप्रतिनिधि के माध्यम से अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की आवाज मजबूती से सुनी जा सकती है और संसद इसकी प्रेरणा का केंद्रबिंदु है। उसके माध्यम से देश में योजनाएं बनती हैं। पांच बार लोकसभा सदस्य रहे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संसद में रहकर सीखा कि सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों, आपसी व्यवहार और नियम के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। विधान सभा–विधान परिषद केवल संसद के नियमों–परिनियमों का अवलोकन–प्रशिक्षण ले ले तो उसे अपने सदन संचालन में काफी आसानी होगी।

संसद के प्रति श्रद्धा का भाव हर भारतवासी का दायित्व

सीएम ने कहा कि सतीश महाना ने 2022 में विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व संभाला तो मैंने उनसे कहा कि प्रश्नकाल में 20 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध होते हैं, लेकिन सवा घंटे के प्रश्नकाल में केवल दो–तीन सदस्य ही बोल पाते हैं। क्या हम भी इसे संसद की तर्ज पर आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर उन्होंने तत्काल नियमावली में परिवर्तन किया। अब सवा घंटे में 20 तारांकित प्रश्न और हर प्रश्न के साथ दो–तीन अनुपूरक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न करने वाले और उत्तर देने वाले मंत्रीगण, दोनों पूरी तैयारी के साथ आते हैं। सदन में अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों की सहभागिता दिखती है। संसद हमारे लिए प्रेरणा बनी। हमारे पास सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में संसद है। यदि हम कुछ कर रहे हैं तो संसद ही उसका आधार बनती है, उसके प्रति श्रद्धा हर भारतवासी का दायित्व है।

एक भाव–एक भंगिमा के साथ बोलता और सोचता है भारत

सीएम योगी ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य 'भारत लोकतंत्र की जननी है' का जिक्र किया, फिर कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि ग्राम स्वराज की परिकल्पना को गांवों ने साकार किया। देश में रूपरंग, खानपान, वेशभूषा अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरा भारत एक भाव–एक भंगिमा के साथ बोलता और सोचता है। उसकी आस्था एक होती है। संसद उस आस्था को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। संसद को आदर्श के रूप में बढ़ाएंगे तो विधायिका और मजबूत–सशक्त होगी।

'विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश' पर 24 घंटे चली चर्चा के सहभागी बने 300 सदस्य

सीएम योगी ने सम्मेलन में पारित हुए छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अभिनंदनीय बताया और कहा कि प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव में आगामी 25 वर्ष की कार्ययोजना बनाने को कहा। 'विजन 2047– विकसित भारत' की परिकल्पना को साकार करने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। सीएम ने कहा कि 'विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत–आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' पर सत्तापक्ष व विपक्ष के 300 से अधिक सदस्य 24 घंटे तक चलने वाली चर्चा के सहभागी बने। चर्चा का शुभारंभ करने के बाद मैं कुछ देर बैठा रहा, फिर अन्य प्रशासकीय कार्यों व बैठकों के लिए जाना पड़ा। रात 11 बजे मैं फिर सदन में आया तो भी यहां बोलने की होड़ दिखी। बहुत अच्छे सुझाव आए। हर व्यक्ति के अनुभव का लाभ अत्यंत प्रभावी होता है। विधानसभा–परिषद में लोगों ने विकास के बारे में मुद्दों को रखा और विकसित भारत के लिए अपनी जिम्मेदारी का भी जिक्र किया। विकसित भारत केवल भारत सरकार, प्रधानमंत्री का ही कार्य नहीं है, हम भी कैसे इस अभियान के सारथी–सिपाही बन सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में भी इस प्रस्ताव को पारित करते हुए, प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों को सार्थक गति प्रदान की है।

सीएम ने 30 बैठकों के प्रस्ताव का किया स्वागत

सीएम ने कहा कि यूपी में सदन की कार्यवाही की प्रशंसा की। कहा, यहां कार्यवाही अत्यंत सुगमता से चलती है। सीएम ने वर्ष में कम से कम 30 बैठकों का प्रस्ताव पारित किए जाने को भी सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि यह संसद और विधानसभा के लिए ही नहीं, बल्कि नगर निकायों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के लिए भी प्रेरणा है। जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि विकास की धुरी बनते हैं। तकनीक के इस युग में हम खुद को पीछे नहीं छोड़ सकते। जब सरकार के सामने यह बात आई कि ई–विधान होना है तो हमने कहा कि तत्काल इसे लागू कीजिए। आज यूपी की विधानसभा–परिषद, कैबिनेट और बजट भी पेपरलेस है। सीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधि भी तकनीक से अपडेट हों, उनके उचित प्रशिक्षण समेत सभी प्रस्ताव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

ज्वलंत मुद्दों पर लगातार चर्चा–परिचर्चा चलाती है यूपी विधानसभा–परिषद

सीएम ने कहा कि यूपी विधानसभा ज्वलंत मुद्दों पर लगातार चर्चा–परिचर्चा चलाती है। स्थायी विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) पर भी यहां लगातार 37–38 घंटे चर्चा हुई। उसके लक्ष्य निर्धारित हुए। मंत्रिमंडल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर कमेटी गठित हुई, जो इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। 26 नवंबर, संविधान दिवस पर मौलिक अधिकारों के साथ ही मूल कर्तव्यों को भी हमने विधानसभा–परिषद में अनवरत चर्चा का विषय बनाया। हम विधायकों से कहते हैं यह चर्चा सीमित नहीं होनी चाहिए, इसे ब्लॉक, क्षेत्र व ग्राम पंचायतों के स्तर तक विस्तारित करिए।

OFFICERS' CONFERENCE
LUCKNOW, UTTAR PRADESH
19-21 JANUARY, 2026

'विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश' के लिए पोर्टल पर आए 98 लाख लोगों के सुझाव

"विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश" की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि हमने विजन डॉक्यूमेंट में जनता से सुझाव लिए। हमारी विधानसभा–परिषद में लगभग 500 जनप्रतिनिधि हैं। इनके साथ ही यूपी के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों समेत समाज के अन्य तबकों से जुड़े 500 लोगों की कार्यशाला की गई। उन्हें सेक्टर दिए, 75 जनपदों के लिए 75 ग्रुप बनाए। सबसे कहा गया कि हर किसी को तीन–तीन संस्थाओं में जाकर युवाओं, किसानों, महिला स्वयंसेवी समूहों समेत विभिन्न तबकों को इस मुद्दे से जोड़कर चर्चा करनी है। "विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश" के लिए पोर्टल पर 98 लाख लोगों के सुझाव आए। एआई टूल के माध्यम से आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर हम उसे फाइनल रूप दे रहे हैं। अलग–अलग सेक्टर में आए सुझावों को विजन डाक्यूमेंट का हिस्सा बनाएंगे। उस विजन डॉक्यूमेंट को लांच करेंगे। इससे हमारी कार्ययोजना के बेहतरीन परिणाम भी आएंगे।

प्रोएक्टिव होता है पीठ और सरकार का अप्रोच

सीएम योगी ने कहा कि पीठ और सरकार का अप्रोच प्रोएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं होता। पीठ ने विपक्ष को अधिक मौका दे दिया तो सरकार रिएक्टिव नहीं होती। पीठ पक्ष–विपक्ष में संतुलन बनाती है। सीएम ने यूपी के विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषद के सभापति के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जहां भी ऐसे सम्मेलन होते हैं, दोनों लोग जाते हैं। वे केवल सदन की कार्यवाही तक सीमित नहीं रहते। सीएम ने ऐसे सम्मेलनों को 'सीखो–सिखाओ' का मंच बताया। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के अलावा विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आए अतिथिगण मौजूद रहे।

जनभागीदारी से और भव्य होगा उत्तर प्रदेश दिवस 2026, अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि : सीएम योगी

संवाददाता

लखनऊ। इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस–2026 को जनोत्सव के रूप में मनाया जाएगा जिसमें प्रदेश के प्रत्येक जनपद की सक्रिय सहभागिता, सांस्कृतिक विविधता और विकास यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। 24 से 26 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन में उत्तर प्रदेश की संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और विकास की उपलब्धियों को जनभागीदारी के माध्यम से एक ही मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा, यह केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश की पहचान, उपलब्धियों और संभावनाओं को जनसहयोग के साथ प्रदर्शित करने का अवसर है। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं में गरिमा, अनुशासन और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे, जिससे आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिलेगी। राजधानी लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मुख्य समारोह आयोजित होगा और इसका सीधा प्रसारण पूरे प्रदेश में किया जाएगा। बयान में कहा गया कि उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 'विकसित भारतदृविकसित उत्तर प्रदेशश की थीम पर विशेष प्रदर्शनी और शिल्प मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश की विकास यात्रा, नवाचार, बुनियादी ढांचा, उद्योग, कृषि, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष 'एक जनपद एक व्यंजन आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगा, जिसमें हर जनपद के पारंपरिक व्यंजन एक ही परिसर में उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने संस्कृति उत्सव 2025–26 के अंतर्गत प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश दिवस से जोड़ने और लोक, शास्त्रीय एवं समकालीन कला रूपों को मंच प्रदान करने के निर्देश दिए। 24 जनवरी के मुख्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि प्रदेश की सामूहिक उपलब्धियों का सम्मान किया जा सके।

अरावली पर एक्सपर्ट की हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे, अवैध खनन ना हो : सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी

नयी दिल्ली। अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश आया है। कोर्ट ने कहा है कि सुनिश्चित करें अरावली क्षेत्र में अवैध खनन ना हो। अवैध खनन के परिणाम ऐसे होते हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सकता। इस तरह की गतिविधियों के दूरगामी और गंभीर परिणाम होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया– 'अरावली को लेकर अलग–अलग फील्ड के और डोमेन एक्सपर्ट की हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे। इस समिति में वैज्ञानिकों, पर्यावरण और वन क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। अरावली रेंज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अब इसको लेकर नई याचिका दायर नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने एमिकस क्यूरी से रिपोर्ट देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट चार सप्ताह बाद इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। कोर्ट ने हाई पावर कमेटी में शामिल होने वाले सदस्यों के नाम सुझाने को भी कहा गया है।सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर नियम से संबंधित अपने पूर्व फैसले पर लगी रोक को आगे बढ़ाया। यह रोक उस फैसले पर है, जिसमें अरावली क्षेत्र में खनन पर 100 मीटर की सीमा तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों, जिनमें एमिकस क्यूरी भी शामिल हैं, से कहा है कि वे प्रस्तावित समिति के लिए अपने सुझाव और विशेषज्ञों के नाम अदालत के समक्ष पेश करें। अदालत ने दोहराया कि अरावली जैसे संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों पर सीधा प्रभाव डालेगी। बता दें कि सीजेआई सूर्यकांत की बेंच अरावली मामले में संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जमीन से 100 मीटर या अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली मानने के नियम पर रोक लगाई थी। लगातार चले रहे प्रदर्शन और विवाद के बीच कोर्ट ने यह फैसला दिया था। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट और कोर्ट की टिप्पणियों के गलत अर्थ निकले जा रहे हैं। इसे दूर करने के लिए स्पष्टीकरण की आवयश्कता है।

मोदी मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, 2031 तक जारी रहेगी अटल पेंशन योजना

अगले 5 साल तक मिलेगा फायदा

एजेंसी

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार की प्रमुख अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को वित्त वर्ष 2030–31 तक जारी रखने को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही प्रचार, विकासात्मक गतिविधियों और गैप फंडिंगश के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार को भी स्वीकृति दी गई है। वित्तीय कमी की पूर्ति को श्गैप फंडिंगश कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए जागरूकता एवं क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों को सरकारी समर्थन मिलता रहेगा। अटल पेंशन योजना की शुरुआत नौ मई 2015 को की गई थी। जिसका मकसद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करना है। विज्ञप्ति के अनुसार, 19 जनवरी 2026 तक एपीवाई के तहत 8.66 करोड़ से अधिक सदस्य पंजीकृत हो चुके हैं। योजना के तहत योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह तक की न्यूनतम पेंशन की गारंटी का प्रावधान है। सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। सरकार ने एक वक्तव्य जारी कर कहा है कि 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी वित्तीय सेवा विभाग द्वारा सिडबी में तीन चरणों में निवेश की जाएगी। इसमें वित्तीय वर्ष 2025–26 में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश 31.03. 2025 के बुक वैल्यू पर प्रति शेयर 568. 65 रुपये किया जाएगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026–27 और 2027–28 में क्रमशः 1,000 करोड़ रुपये, 1,000 करोड़ रुपये की राशि संबंधित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की बुक वैल्यू पर निवेश की जाएगी। इससे 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी निवेश के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लघु इकाइयों (एमएसएमई) की संख्या वित्तीय वर्ष 2025 के अंत में 76.26 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2028 के अंत तक 102 लाख (अर्थात लगभग 25. 74 लाख नए एमएसएमई लाभार्थी जोड़े जाएंगे) होने की उम्मीद है।

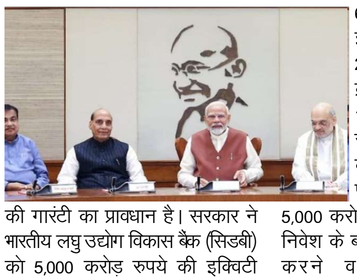

आम लोगों के लिए इस दिन से खुलेगा अमृत उद्यान, राष्ट्रपति सचिवालय ने दी जानकारी

एजेंसी

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति सचिवालय ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान तीन फरवरी से 31 मार्च 2026 तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। लोग सप्ताह में छह दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक (अंतिम प्रवेश 5.15 बजे) उद्यान आ सकते हैं। मंगलवार को उद्यान बंद रहेगा, क्योंकि उस दिन रखरखाव का काम होता है। साथ ही होली के कारण चार मार्च को भी उद्यान बंद रहेगा। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान तीन फरवरी से 31 मार्च 2026 तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान में प्रवेश और बुकिंग निःशुल्क है और राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से बुकिंग की जा सकती है। सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास राष्ट्रपति भवन परिसर के गेट नंबर 35 से होगा। आगंतुकों की सुविधा के लिए, केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक शटल बस सेवा सुबह साढ़ नौ बजे से शाम छह बजे के बीच हर 30 मिनट पर उपलब्ध रहेगी। शटल बसों को अमृत उद्यान के लिए शटल सेवा बैनर से पहचाना जा सकता है।

संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर कसा शिकंजा, शारिक साटा की संपत्ति कुर्क

एजेंसी

मुरादाबाद। संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में मुख्य साजिशकर्ता दीपा सराय निवासी शारिक साटा की संपत्ति कुर्क की जा रही है। भारी संख्या में पुलिसबल तैनात है। कुर्की का आदेश कोर्ट से होने के बाद कार्रवाई की गई है। हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक के घर पर कोर्ट के आदेश पर उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए भारी पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। तहसीलदार धीरेंद्र कुमार ने कहा कि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, शारिक की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं, यह प्रॉपर्टी शहर के सबसे महंगे इलाकों में से एक में है। इस बिल्डिंग में चार मंजिलें हैं, लेकिन सिर्फ फरार आरोपी की मिल्कियत वाली मंजिल को ही अटैच किया गया है।कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शारिक के घर को अटैच कर लिया है। बवाल में मुख्य साजिशकर्ता आरोपी शारिक साटा के खिलाफ धारा 209 बीएनएस के तहत तीन रिपोर्ट दर्ज की गई थीं। यह कार्रवाई न्यायालय में हाजिर नहीं होने के चलते की जाती है। इसी क्रम में अब कोर्ट द्वारा कुर्की का आदेश किया गया है। एसपी ने बताया कि शारिक साटा के खिलाफ मुख्य अपराध संख्या 340ध्24 और 306ध्24 में हत्या की साजिश करने, बवाल की साजिश रचने व अन्य गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। साटा के गिरोह के सदस्य मुल्ला अफरोज, गुलाम और वारिस ने बवाल के दौरान गोलियां चलाई थीं। इसमें आम लोगों की मौत हो गई थी। अज्ञात में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इस गिरोह की भूमिका मिलने पर तीनों गुर्गों को गिरफ्तार किया था। इसमें मुल्ला अफरोज के खिलाफ एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है।

संपादकीय

मददवीर अग्निवीर

सेना में अग्निवीर योजना के क्रियान्वयन के वक्त इनकी अल्पकालिक सेवा और सेवानिवृत्ति के बाद उनके भविष्य को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं। लेकिन अब धीरे–धीरे कई आशंकाएं निर्मूल साबित हो रही हैं। प्रशिक्षित अग्निवीरों के लिये नये–नये अवसर बन रहे हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में गठित होने जा रही डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। यह सुखद ही है कि अग्निपथ योजना के पहले बैच के सेवा काल की समाप्ति से पहले हरियाणा सरकार ने उनके समायोजन की पहल की है, जिसका अनुकरण देश के अन्य राज्यों को भी करना चाहिए। जिससे इस कुशल–प्रशिक्षित युवा शक्ति की ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल की पहल हो सके। दरअसल, हरियाणा में स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में अग्निवीरों को वरीयता देने की बात कही गई है। निश्चय ही इस कदम से जहां अग्निवीरों की नई पीढ़ी सामने आएगी, वहीं राज्य को इनके कुशल प्रशिक्षण का लाभ मिल सकेगा। यह भी हकीकत है कि बदलते वक्त के साथ आपदाओं की पुनरावृत्ति व घातकता बढ़ रही है, उससे जूझने के लिये भी अनुभवी व प्रशिक्षित बल की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। जो एक स्थायी, पेशेवर और पूर्णकालिक बल के जरिये ही संभव हो सकता है। दरअसल, हरियाणा में सरकार ने भरोसा दिलाया है कि राज्य में गठित होने वाली एसडीआरएफ बटालियन में अधिकतम संख्या अग्निवीरों की ही होगी। विश्वास किया जा रहा है कि अग्निवीरों वाली एसडीआरएफ प्राकृतिक आपदाओं मसलन बाढ़,भूकंप, औद्योगिक दुर्घटनाओं, अग्निकांडों व रासायनिक आपदाओं की चुनौती का सफलता से मुकाबला कर सकेगी। माना जा रहा है कि अग्निवीरों को मिला कठोर प्रशिक्षण आपातकालीन स्थितियों से मुकाबले में मददगार साबित होगा। दरअसल, ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में तीव्र गति से कार्रवाई करते नागरिकों के जीवन की रक्षा करने की प्राथमिकता होती है। जो प्रशिक्षित और अनुभवी टीम के द्वारा ही संभव हो सकता है। कहा जा रहा है कि राज्य की सभी डिविजनों में क्विक रिस्पॉन्स टीम तैनात की जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में नोएडा में धुंध के चलते हुई एक सड़क दुर्घटना में एक युवा इंजीनियर की मौत हुई। बेटे को मौत के मुंह में समाते देख असहाय पिता ने पुलिस से मदद मांगी। लेकिन मदद के लिये पहुंची टीम के पास इस चुनौती का मुकाबला करने के लिये जरूरी उपकरण व अनुभव नहीं था। ऐसे में युवा इंजीनियर ने पिता के सामने ही डूबकर दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद आपदा राहत बल को प्रशिक्षित करने और जीवन रक्षा के तमाम उपकरण उपलब्ध कराने की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में हरियाणा में एसडीआरएफ बटालियन के गठन और उसमें प्रशिक्षित व अनुभवी अग्निवीरों की तैनाती की घोषणा के बाद उम्मीद जगी है कि हरियाणा की सुरक्षा कुशल हाथों में रहेगी। तब प्राकृतिक, औद्योगिक व आगजनी आदि की घटनाओं में जन–क्षति को कम करने में मदद मिल सकेगी। हालांकि, अब तक हरियाणा में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आईआरबी की बटालियन पहले ही नोडल डिजास्टर रिस्पॉन्स एजेंसी के रूप में सक्रिय रही है। इसके अंतर्गत सैकड़ों कर्मचारियों को आपदाओं से निबटने के लिये प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लेकिन आपदाओं व दुर्घटनाओं की घातकता के मद्देनजर स्पेशल व स्थायी बल की आवश्यकता लगातार महसूस की जाती रही है। विश्वास किया जाना चाहिए कि अनुभवी नेतृत्व में प्रशिक्षित टीम व आधुनिक जीवन रक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाने से एसडीआरएफ तमाम चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हो सकेगी। निश्चित रूप से अग्निवीरों की सेना में कुशल ट्रेनिंग, अनुशासन के साथ चुनौतियों का मुकाबला करने का प्रशिक्षण व फील्ड में हासिल अनुभव स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को प्रभावी बनाएगा। जिसके आधार पर ही सरकार ने उन्हें एसडीआरएफ बटालियन में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। निश्चित तौर पर इससे राज्य में आपदा में तुरंत प्रतिक्रिया क्षमता को संबल मिलेगा। साथ ही अग्निवीरों को अपनी क्षमता प्रदर्शन का नया मंच मिलने से, युवा सेना की अग्निवीर योजना को कैरियर के विकल्प के रूप में चुन सकेंगे।

जब पढ़ा खड़ा हो और अनपढ़ बैठा हो : लोकतंत्र में शिक्षा का अपमान

—डॉ. सत्यवान सौरभ

किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसकी शिक्षा.व्यवस्था और उस शिक्षा को मिलने वाले सम्मान से होती है। शिक्षा केवल डिग्रियों का संग्रह नहीं, बल्कि विवेक, अनुशासन, संवैधानिक समझ और सार्वजनिक जिम्मेदारी का संस्कार है। सवाल यह है कि क्या भारत जैसा लोकतंत्र सचमुच इस शिक्षा का सम्मान कर रहा है, या सत्ता के गलियारों में पढ़े.लिखे लोग केवल आदेश पालन की मुद्रा में खड़े रहने के लिए ही नियत कर दिए गए हैं। भारत में लाखों युवा वर्षों तक कठिन तैयारी, असफलता और संघर्ष के बाद सिविल सेवाओं तक पहुँचते हैं। वे संविधान, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र और नीति.निर्माण के गंभीर अध्ययन के बाद आईएएस, आईपीएस या अन्य सेवाओं में आते हैं। चयन के बाद भी लंबा प्रशिक्षण, फील्ड पोस्टिंग और निरंतर जवाबदेही उनका हिस्सा होती है। दूसरी ओर कई बार वही अफसर ऐसे जनप्रतिनिधियों के सामने हाथ बाँध कर खड़े दिखते हैं, जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रशासनिक समझ बेहद सीमित होती है। यही वह दृश्य है, जहाँ व्यंग्य नहीं, व्यवस्था की सच्चाई बोलती हैकृअनपढ़ बैठे हैं, पढ़ा खड़ा है। एक सिविल सेवक बनने की यात्रा वर्षों की साधना है। परीक्षा केवल तथ्यों का नहीं, सोचने की क्षमता, विश्लेषण, नैतिकता और दबाव में निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण करती है। सेवा में आने के बाद भी हर फाइल, हर आदेश, हर हस्ताक्षर भविष्य की जांच.परख की कसौटी पर खरा उतरना होता है। इसके उलट, राजनीति में प्रवेश के लिए न किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त है, न नीति या प्रशासन का औपचारिक प्रशिक्षण अनिवार्य है। जनसमर्थन लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन जब वही जनसमर्थन पूरे तंत्र में योग्यता के अभाव को ढकने का आवरण बन जाए, तब समस्या शुरू होती है। लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन है, लेकिन लोकतंत्र कभी भी अज्ञान का उत्सव नहीं रहा। सफल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक नेतृत्व और पेशेवर प्रशासन, दोनों को महत्व दिया गया है। वहाँ निर्णय लेने के मंच पर भावनाएँ नहीं, तथ्यों और तर्क की भी जगह होती है। हमारे यहाँ स्थिति यह बनती जा रही है कि बहस में शोर अधिक है, अध्ययन कम। आरोप. प्रत्यारोप की गर्मी अधिक है, आंकड़ों. तथ्यों की रोशनी कम। ऐसे माहौल में अफसरशाही, जो ज्ञान और प्रक्रिया की प्रतिनिधि है, केवल आदेश मानने वाली मशीन तक सीमित कर दी जाती है। यही मानसिकता उस दृश्य को जन्म देती हैकृकुर्ता बैठा है, वर्दी खड़ी है। स्वतंत्र भारत की कल्पना में खादी और खाकी एक. दूसरे के पूरक माने गए थे। खादी जनमत, राजनीति और नीति.निर्माण का प्रतीक थी, खाकी कानून, व्यवस्था और निष्पक्ष क्रियान्वयन की। दोनों के बीच सम्मान आधारित रिश्ते से ही सुशासन की नींव रखी जानी थी। आज स्थिति यह है कि खादी कई बार संख्या.बल और पद की शक्ति के सहारे अपनी बात थोपती दिखती है, और खाकी स्थानांतरण, प्रतिशोध या झूठे आरोपों के डर से विवेकपूर्ण सलाह देने से कतराने लगती है। अफसर यह सोचने लगे हैं कि "सही क्या है" से ज़्यादा महत्वपूर्ण "ऊपर क्या चाहते हैं" है। यह मानसिकता न केवल प्रशासनिक नैतिकता को कमजोर करती है, बल्कि कानून के राज पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। इस वातावरण का सीधा असर समाज में शिक्षा की छवि पर पड़ता है। जब युवाओं को बार.बार यह दृश्य दिखता है कि जिसने वर्षों पढ़ाई की, प्रतियोगी परीक्षाएँ पास कीं, प्रशिक्षण लिया, वही अंत में केवल खड़ा है; और जिसने बिना किसी तैयारी के राजनीति की सीढ़ी चढ़ ली, वही बैठ कर अंतिम निर्णय ले रहा है, तो स्वाभाविक रूप से निराशा जन्म लेती है। संदेश साफ़ होता है–शिक्षा से सत्ता नहीं मिलती, ज्ञान से निर्णय नहीं होते और मेहनत से सम्मान सुनिश्चित नहीं। धीरे.धीरे शिक्षा समाज को दिशा देने का माध्यम नहीं, केवल नौकरी पाने का जरिया बनकर रह जाती है। विडंबना यह भी है कि जब नीतियाँ असफल होती हैं, योजनाएँ धरातल पर नहीं उतरतीं या भ्रष्टाचार सामने आता है, तो सबसे पहले निशाने पर भी अफसर ही होते हैं। वास्तविकता यह है कि अधिकतर बड़े फैसले राजनीतिक स्तर पर लिए जाते हैं, अफसर उस नीति के क्रियान्वयनकर्ता होते हैं। फिर भी असफलता की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर पर डाल दी जाती है। यह दोहरा अन्याय हैकृनिर्णय में भागीदारी सीमित, लेकिन जवाबदेही पूरी। परिणाम यह होता है कि ईमानदार और साफ.गोई से काम करने वाले अधिकारी हतोत्साहित होते हैं और "चुप रहना, जो कहा जाए वही करना" सुरक्षित विकल्प बन जाता है। जब भी यह सवाल उठाया जाता है कि क्या नीति.निर्माण के लिए न्यूनतम शिक्षा और प्रशासनिक समझ आवश्यक होनी चाहिए, तब तुरंत तर्क दिया जाता है कि "क्या आप जनप्रतिनिधियों की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं?" साफ़ होना चाहिए कि सवाल वैधता का नहीं, क्षमता का है। जनप्रतिनिधि जनता के वोट से आते हैं, यह उनकी लोकतांत्रिक वैधता है और इसका सम्मान जरूरी है। लेकिन क्या जनादेश अपने आप में हर क्षेत्र की विशेषज्ञता का प्रमाणपत्र है? क्या करोड़ों लोगों पर असर डालने वाले निर्णय केवल राजनीतिक चतुराई, जातीय समीकरण या चुनावी लाभ. हानि को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए? सवाल सीधा हैकृयदि डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, यहां तक कि एक साधारण क्लर्क की नौकरी के लिए भी योग्यता और परीक्षा जरूरी है, तो एक बड़े मंत्रालय का नेतृत्व बिना किसी प्रशिक्षण और न्यूनतम बौद्धिक तैयारी के कैसे सम्भव माना जा सकता है? लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं कि "जो चुन कर आए, वह सब जानता ही होगा"; लोकतंत्र का अर्थ यह है कि चुना हुआ नेतृत्व विशेषज्ञों, प्रशासनिक अनुभव और संवैधानिक मूल्यों की मदद से निर्णय ले। समाधान अफसरों को सर्वोच्च बना देने में नहीं है, न ही जनप्रतिनिधियों को कमतर साबित करने में। समाधान संतुलन में है। जनप्रतिनिधि नीति की दिशा तय करें, प्राथमिकताएँ निर्धारित करें; अफसर उस दिशा को संवैधानिक ढांचे और प्रशासनिक व्यावहारिकता के अनुरूप आकार दें। इसके लिए कुछ कदम आवश्यक हैंकृजनप्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य संवैधानिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण, नए विधायकों और मंत्रियों के लिए व्यवस्थित ओरिएंटेशन प्रोग्राम, समितियों में विशेषज्ञों और शोध संस्थानों की सक्रिय भागीदारी, तथा अफसरशाही को ऐसी पेशेवर स्वतंत्रता, जहाँ वह भय नहीं, विवेक के साथ सलाह दे सके। सबसे ज़रूरी यह स्वीकार करना है कि शिक्षा को केवल परीक्षा.कक्ष तक सीमित नहीं रखा जा सकता; उसे निर्णय.कक्ष तक भी पहुँचाना होगा। लोकतंत्र में सवाल पूछना, योग्यता की बात करना या शिक्षा का सम्मान मांगना, लोकतंत्र. विरोधी नहीं, बल्कि लोकतंत्र.समर्थ कदम हैं। जनता का जनादेश सर्वोच्च है, लेकिन वही जनादेश यह भी चाहता है कि निर्णय सोच.समझ कर, तथ्यों और तर्क के आधार पर हों। जब तक यह दृश्य बना रहेगा–अनपढ़ बैठे हैं, पढ़ा खड़ा है; कुर्ता बैठा है, वर्दी खड़ी है; खादी बैठी है, खाकी खड़ी हैकृतब तक यह कहना कठिन होगा कि हमने शिक्षा को सचमुच सम्मान दिया है। लोकतंत्र का उद्देश्य केवल सत्ता.हस्तांतरण नहीं, विवेकपूर्ण शासन है। और विवेक शिक्षा, ज्ञान और योग्यता से ही आता है। भारत यदि सचमुच एक परिपक्व लोकतंत्र बनना चाहता है, तो उसे तय करना होगा कि वह शिक्षा को केवल डिग्री और नौकरी तक सीमित रखेगा, या उसे शासन और नीति.निर्माण के केंद्र तक पहुँचने देगा। जिस दिन पढ़ा.लिखा केवल खड़ा नहीं, बल्कि सम्मान के साथ निर्णय लेते हुए दिखाई देगा, उसी दिन कहा जा सकेगा कि इस देश में शिक्षा का मज़ाक नहीं, उसका सम्मान हो रहा है।

सहेजना ज़रूरी है, पर कितना? संचय प्रवृत्ति का द्वंद्व

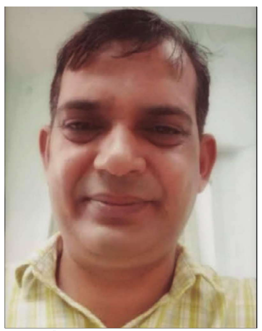

—सुनील कुमार महला

मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह इस जीवन को स्थायी मानकर चलने लगता है। वह सोचता है कि जितना अधिक वह संचय कर लेगा–धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा या संबंध–उतना ही उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। वास्तव में, इसी सोच के कारण वह निरंतर संग्रह में लगा रहता है। परंतु संचय की यह प्रवृत्ति, जब आवश्यकता से अधिक(बहुत अधिक संचय की भावना)हो जाती है, तब वह जीवन को सरल नहीं बल्कि बोझिल बना देती है। मनुष्य का मन धीरे–धीरे इच्छाओं, भय और असंतोष से भरने लगता है। वह आज में जीना भूलकर कल की चिंता में अपना वर्तमान खो देता है। हालांकि, कुछ हद तक व्यक्ति को संचय करना ठीक है, जैसा कि भविष्य की आवश्यकता हेतु संचय, विपत्ति हेतु संचय,आने वाले कल हेतु संचय आदि। संस्कृत में एक श्लोक में कहा गया है कि–श्अद्य कृत्वा न कर्तव्यं कर्तव्यमद्य एव तत। भविष्ये निश्चयं कृत्वा संचयं कुरु बुद्धिमान्ध्श अर्थात् इसका मतलब यह है कि आज जो करना आवश्यक है, उसे आज ही करो। भविष्य को ध्यान में रखकर बुद्धिमान व्यक्ति संचय करता है।विपत्ति में भी संचय का महत्व है, क्यों कि संचित धन विपत्ति में मित्र के समान सहायक होता है; बिना संचय के कोई सहारा नहीं रहता। इसीलिए संस्कृत में कहा गया है–श्संचितं हि भवेद् वित्तं विपत्तौ मित्रवत् सदा। असंचितस्य लोकेऽस्मिन् नास्ति कश्चित् सहायःघ्श लेकिन आज का व्यक्ति हरदम,हर पल पदार्थ में रचा–बसा नजर आता है।वह ज्यादा से ज्यादा संचय कर लेना चाहता है,आवश्यकता से बहुत अधिक संचय। थोड़ा–थोड़ा संचय करना ठीक है।इस संबंध में,संचय ग़र करना ही है तो व्यक्ति को मधुमक्खी से शिक्षा (थोड़ा–थोड़ा संचय) की शिक्षा लेनी चाहिए।जैसे मधुमक्खी प्रतिदिन थोड़ा–थोड़ा मधु संचित करती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति नियमित रूप से संचय करता है। बड़े खूबसूरत शब्दों में कहा गया है–श्यथा मधुकरो नित्यं मधु संगृह्य गच्छति।तथा बुद्धिमान् नित्यं अल्पमल्पं संचिनोतिघ्श कहना ग़लत नहीं होगा कि आदमी की संचय करने के पीछे आने वाले कल की सोच निहित होती है। कहते हैं कि जिसने पहले से संचय कर लिया, उसे भविष्य का शोक नहीं होता। संस्कृत में कहा गया है कि–श्न हि भविष्यतः शोकः कृतसंचयमेव हि।बुद्धिमान् स भविष्याय पूर्वमेव संचिनोतिघ्श हालांकि, इसके विपरीत प्रकृति हमें बिल्कुल भिन्न संदेश देती है। पक्षियों के जीवन को देखें। वे कभी संचय नहीं करते। न उनके पास गोदाम होते हैं, न तिजोरियाँ। हर सुबह वे खुले आकाश में निकल पड़ते हैं–नई खोज, नए दाने और नए अनुभव की तलाश में। उन्हें यह चिंता नहीं सताती कि कल क्या होगा या परसों क्या मिलेगा। वे जानते हैं कि आज का दिन आज के लिए है। शाम होते–होते, दिन भर की उड़ान और संघर्ष के बाद, वे अपने छोटे–से घोंसलों में लौट आते हैं और शांति से विश्राम करते हैं। उनका घोंसला भी संग्रह का स्थान नहीं, बल्कि विश्राम और सुरक्षा का प्रतीक होता है। वास्तव में, पक्षियों का यह जीवन हमें यह सिखाता है कि विश्वास और संतोष कितने महत्वपूर्ण हैं। वे प्रकृति पर भरोसा करते हैं और अपने श्रम पर भी। उन्हें भविष्य की अनिश्चितता डराती नहीं, क्योंकि वे वर्तमान में पूरी निष्ठा से जीते हैं। अगली सुबह फिर वही उल्लास, वही चहचहाहट और वही नई शुरुआत होती है। उनके जीवन में भय कम और स्वतंत्रता अधिक होती है।मनुष्य यदि चाहे तो पक्षियों से बहुत कुछ सीख सकता है। संचय आवश्यक है, परंतु सीमा में। आवश्यकता और लालच के बीच का अंतर समझना ही जीवन की परिपक्वता है। जब संचय ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है, तब आनंद, प्रेम और शांति पीछे छूट जाते हैं। मनुष्य स्वयं द्वारा बनाए गए भंडार का रक्षक बनकर रह जाता है, जबकि जीवन उससे कहीं अधिक विशाल और प्रवाहमय है। सच्चा सुख अधिक जमा करने में नहीं, बल्कि कम में संतोष ढूँढने में है। पक्षियों की तरह हर दिन को एक नई यात्रा मानकर, पूरे मन से जीना ही जीवन की सार्थकता है। आज का श्रम, आज का आनंद और शाम का विश्राम–यही जीवन की सरल, सुंदर और संतुलित लय है। यदि मनुष्य इस लय को समझ ले, तो उसका जीवन भी हल्का, मुक्त और आनंदपूर्ण हो सकता है। अंत में निष्कर्ष के तौर पर यही कहूंगा कि संचय जीवन में सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता देता है, इसलिए यह आवश्यक है। लेकिन जब संचय आवश्यकता से अधिक होकर लोभ, संसाधनों की बर्बादी या दूसरों के अभाव का कारण बन जाए, तो वह अनुचित हो जाता है। अतः संतुलित और उद्देश्यपूर्ण संचय ही उचित माना जाना चाहिए।

वर्दी, मर्यादा और विश्वास का संकट

—डॉ. प्रियंका सौरभ

लोकतंत्र में सत्ता का सबसे संवेदनशील और प्रभावशाली चेहरा पुलिस व्यवस्था होती है। पुलिस केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं, बल्कि राज्य की नैतिक शक्ति का प्रतीक भी है। जब इसी व्यवस्था का कोई शीर्ष अधिकारी गंभीर नैतिक आरोपों में घिरता है, तो सवाल केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे तंत्र की साख, जवाबदेही और आचरण पर उठ खड़े होते हैं। कर्नाटक के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और डीजीपी (सिविल राइट्स एन्फोर्समेंट) को कथित आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद निलंबित किया जाना इसी गहरे संकट की ओर संकेत करता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित वीडियो क्लिप्स ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। राज्य सरकार द्वारा त्वरित निलंबन का निर्णय इस बात का संकेत है कि मामला केवल निजी आचरण तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि सार्वजनिक पद की गरिमा और संस्थागत प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ समझा गया। हालांकि, यह भी उतना ही आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनन दोषी ठहराने से पहले निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। लोकतंत्र का यही संतुलन हैकृन तो आरोपों को नज़रअंदाज़ करना और न ही जांच से पहले निर्णय सुना देना। पुलिस वर्दी एक साधारण पोशाक नहीं होती। यह नागरिकों और राज्य के बीच विश्वास का प्रतीक होती है। विशेष रूप से डीजीपी स्तर का अधिकारी केवल आदेश देने वाला प्रशासक नहीं, बल्कि पूरे बल के लिए नैतिक मानक तय करने वाला चेहरा होता है। उसके आचरण से यह संदेश जाता है कि व्यवस्था किस दिशा में खड़ी है। जब किसी शीर्ष अधिकारी पर ऐसे आरोप लगते हैं, तो आम नागरिक के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि नीति निर्धारण और अनुशासन लागू करने वाले ही मर्यादाओं को लेकर लापरवाह हों, तो व्यवस्था से न्याय की उम्मीद कैसे की जाए? यही वह बिंदु है जहाँ व्यक्तिगत आचरण सार्वजनिक चिंता का विषय बन जाता है। यह प्रकरण एक और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता हैकृसोशल मीडिया का प्रभाव। आज किसी भी कथित वीडियो या सामग्री का कुछ ही घंटों में व्यापक प्रसार हो जाता है। इससे एक ओर पारदर्शिता बढ़ी है, तो दूसरी ओर अफवाह, संपादन और दुरुपयोग का खतरा भी। इसलिए राज्य और जांच एजेंसियों के सामने दोहरी चुनौती होती हैकृजनभावना का सम्मान करते हुए भी तथ्यों की गहराई से पड़ताल करना। सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री को आधार बनाकर प्रशासनिक कार्रवाई करना एक संवेदनशील निर्णय होता है। कर्नाटक सरकार द्वारा निलंबन का फैसला यह दर्शाता है कि प्रारंभिक स्तर पर ही जवाबदेही तय करने की कोशिश की गई, ताकि जांच निष्पक्ष वातावरण में हो सके। निलंबन स्वयं में दंड नहीं, बल्कि जांच के लिए रास्ता साफ करने की प्रक्रिया हैकृ यह तथ्य समझना भी जरूरी है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि किसी अधिकारी का निजी जीवन उसके काम से अलग होना चाहिए। सिद्धांत रूप में यह बात सही लग सकती है, लेकिन उच्च संवैधानिक या प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों के लिए निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। कारण साफ है–उनका हर आचरण संस्था की छवि से जुड़ जाता है। यदि कथित कृत्य ऐसे हों जो सार्वजनिक नैतिकता, महिला सम्मान या पद की गरिमा के विपरीत माने जाएँ, तो उन्हें केवल "निजी मामला" कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। विशेषकर तब, जब वे कृत्य सार्वजनिक प्रतीकों, वर्दी या आधिकारिक वातावरण से जुड़े होने का आरोप झेल रहे हों।

इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा प्रश्न व्यक्ति से आगे जाकर संस्थागत जवाबदेही का है। क्या हमारी प्रशासनिक संरचना में ऐसे तंत्र पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, जो समय रहते आचरण संबंधी विचलनों को पहचान सकें? क्या वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आंतरिक आचार संहिता केवल कागज़ों तक सीमित रह गई है? आईपीएस जैसे प्रतिष्ठित कैडर से समाज अपेक्षा करता है कि वह न केवल कानून लागू करे, बल्कि नैतिक नेतृत्व भी प्रदान करे। यदि किसी एक अधिकारी की कथित चूक पूरे बल की छवि पर प्रश्नचिह्न लगा देती है, तो यह संकेत है कि आंतरिक निगरानी और नैतिक प्रशिक्षण पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह होता है कि कानून सबके लिए समान है। चाहे वह आम नागरिक हो या सर्वोच्च पद पर बैठा अधिकारी। यदि जांच के बाद आरोप सिद्ध होते हैं, तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो यह स्पष्ट करे कि पद, प्रभाव और पहचान कानून से ऊपर नहीं हैं। साथ ही, यदि आरोप असत्य या बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए पाए जाते हैं, तो यह भी उतना ही आवश्यक है कि संबंधित अधिकारी की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया जाए। न्याय का अर्थ केवल दंड देना नहीं, बल्कि सत्य की स्थापना भी है। आम नागरिक पुलिस से केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि नैतिक आश्वासन भी चाहता है। वह यह विश्वास करना चाहता है कि जिन हाथों में कानून की बागडोर है, वे स्वयं कानून और मर्यादा के दायरे में हैं। जब ऐसे प्रकरण सामने आते हैं, तो जनता का भरोसा डगमगाता है–और यही किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। इसलिए सरकारों और संस्थानों की जिम्मेदारी केवल तात्कालिक कार्रवाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह भी सोचना होगा कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न होकृ इसके लिए प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक परामर्श, नैतिक मूल्यांकन और जवाबदेही की स्पष्ट प्रक्रियाएँ विकसित करनी होंगी। कर्नाटक डीजीपी प्रकरण केवल एक अधिकारी के कथित आचरण का मामला नहीं है। यह उस व्यापक प्रश्न का प्रतीक है कि सत्ता, नैतिकता और जवाबदेही के बीच हमारा संतुलन कितना मजबूत है। निलंबन एक प्रारंभिक कदम है, अंतिम निष्कर्ष नहीं। असली कसौटी निष्पक्ष जांच, पारदर्शी प्रक्रिया और न्यायसंगत निर्णय में होगी। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब संस्थाएँ स्वयं को सुधारने का साहस दिखाती हैं। वर्दी की गरिमा, पद की मर्यादा और जनता का विश्वासकृइन तीनों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि कानून बिना भय और पक्षपात के अपना काम करे। यही इस पूरे प्रकरण से निकलने वाला सबसे महत्वपूर्ण संदेश होना चाहिए।

राशिफल

मेष :– नई सफलताओं से खुद की क्षमताओं का ऐहशास होगा। जीविका क्षेत्र में अवरोधों से मन में निराशा संभव भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में ब्यय की अपेक्षित है। सन्तत्ति एवं सन्तानोत्पत्ति के लिए प्रयास सार्थक होंगे।

बृषभः– शासन–सत्ता कें लोगों के साथ निकटता बढ़ेगी। नियोजित परिश्रम द्वारा कार्य सिद्धी के आसार बनेंगे। पुराने संबंधों से लाभ संभव। परिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा।

मिथुनः– कठिन एवं विषम परिस्थितियों के मध्य परिश्रम व लगन से प्रगति के ओर अग्रसर होंगे। समाजिक सक्रीयता से मान–प्रतिष्ठा में बृद्धि होगी। घरेलू दायित्वो के प्रति आपकी महत्ता बढ़ेगी।

कर्कः– कुछ भौतिक आकांक्षाएं अपनी सार्थकता हेतु मन को उद्वेलित करेंगी। निकटस्थ सम्बन्धों में भावनात्मक अपेक्षाएं कष्टकारी हो सकती है। तामसी व गैर कायरे पर आकर्षित मन पर अंकुश लगावें।

सिंहः– कुछ नई इच्छाएं बलवती होंगी। प्रयासरत् क्षेत्रों में संघर्ष संभव परन्तु निराशावादी बिचारों को मन में स्थान न दें। किसी बड़े आयोजन हेतु समुचित ब्यवस्था के लिए मन प्रयत्नशील होगा।

कन्याः– नकारात्मक चिन्ताओं को त्याग कर अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। नौकरी–पेशे में अधिकारियों व सहकर्मियों के सहयोग से वातावरण सुखद होगा। राजनैतिक क्षेत्र के ब्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा।

तुलाः– किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लाएगी। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव। दुबिधाओं को त्याग कर सही व स्वच्छ योजनाओं पर केन्द्रित हों।

वृश्चिकः– कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ मन पर प्रभावी होंगी। घरेलू कायरे में ब्यस्तता बढ़ेगी। परिजनों के सहयोग से मन उत्साहित होगा। हंसमुख स्वभाव से आस–पास वातावरण में प्रसन्नता बिखेरेंगे।

धनुः– सम्बन्धों में ब्यवहारकुशल बनें। समाजिक व मांगलिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी संभव। कुछ महत्वपूर्ण प्रयत्न की सार्थकता आप में नए उत्साह का संचार करेगा।

मकरः– बिद्यार्थियों के लिए ग्रहों की अनुकूलता लाभप्रद होगी। कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं सार्थक होगी। नवीन आशाएं नवीन उत्साह लाएंगी। कार्य क्षेत्र में सम्बन्धों का भरपूर लाभ मिलेगा।

कुंभः– अन्तमरुखी स्वभाव को त्याग बहिरमुखी बनें। कुछ महत्वपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति के आसार हैं। परिजनों के सुख–दुख के प्रति मन चिन्तित होगा। कार्य क्षेत्र में ब्यस्तता बढ़ेगी।

मीनः– पुरानी समस्याओं पर बिजय प्राप्त कर सुखद अनुभूति करेंगे। ग्रहों की अनुकूलता से कोई अवरोधित कार्य हल होने के आसार बनेंगे। समुचित परिश्रम करने में असमर्थ मन परेशान होगा।

जे.पी. नड्डाः एक शांत रणनीतिकार की विदाई

के.एस. तोमर

यह एक अनुभवी राजनेता जगत प्रकाश नड्डा के लिए भावुक विदाई है, एक ऐसी विदाई, जो राजनीतिक विडंबनाओं और उपलब्धियों के अनोखे संगम से सजी है। हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत के बाद महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में मिली निर्णायक सफलता ने इस विदाई को राजनीतिक पुनर्स्थापन और संगठनात्मक विजय के पुष्पगुच्छ में बदल दिया। अस्थिर राजनीति के बीच कार्यकाल रू औपचारिक रूप से उनका कार्यकाल संतोष, आत्मविश्वास और शांत गर्व की अनुभूति कराता है। राजनीतिक अस्थिरता के दौर में पार्टी की कमान संभालते हुए उन्होंने न केवल संगठन की वैचारिक जड़ों को मजबूत किया बल्कि भाजपा के चुनावी विस्तार को नए क्षेत्रों तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में भाजपा ने अपने पारंपरिक गढ़ों को और सुदृढ़ किया, जिससे वह भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में और स्थापित हुई। नड्डा का कार्यकाल शांत परिश्रम, रणनीतिक जमीनी संगठन और वैचारिक अनुशासन के साथ डिजिटल नवाचार के संतुलन के लिए जाना जाएगा। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु बनाते हुए पार्टी को उसकी मूल हिंदुत्व विचारधारा में दृढ़ रखा और साथ ही डाटा–आधारित, तकनीक–सक्षम चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाया। कोविड–19 महामारी के दौरान उनका नेतृत्व विशेष रूप से परखा गया, जब उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को देशव्यापी राहत और सेवा कार्यों के लिए संगठित किया।

यूपी ने मिटाया 'बीमारू राज्य' का दाग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने दुनिया को दिखाया विकास का नया मॉडल

कायम की नई मिसाल, तस्वीर के साथ तकदीर भी बदली उत्तर प्रदेश की

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। हर वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल प्रदेश के गठन की स्मृति मात्र नहीं है, वरन यह आत्ममंथन का भी अवसर है कि उत्तर प्रदेश आज कहां खड़ा है और किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश को देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा जाता था। बदहाल कानून–व्यवस्था, कमजोर बुनियादी ढांचा, पलायन करती आबादी और निवेशकों की उदासीनता इस पहचान का सबसे बड़ा कारण थी। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश की तस्वीर और तकदीर, दोनों में उल्लेखनीय ठोस बदलाव परिलक्षित होने लगे। जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली तब उन्हें मात्र 12.88 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश मिला था, जिसे उनकी सरकार ने अपने पौने नौ वर्षों के कार्यकाल में लगभग 31 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचा दिया है। अब उन्होंने 2029–30 तक उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।

कानून–व्यवस्था से शुरुआत बदले विश्वास की बुनियाद

सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने सबसे पहले अपना खास ध्यान कानून–व्यवस्था पर केंद्रित किया। संगठित अपराध, माफिया राज और दंगों की राजनीति ने उत्तर प्रदेश की छवि को लंबे समय तक हानि पहुंचाने का काम किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दिया कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, पुलिस सुधार अभियानों, संगठित अपराधियों पर कार्रवाई और माफिया की संपत्तियों की जब्ती ने अपराधियों का मनोबल तोड़ने के साथ–साथ आम नागरिकों और निवेशकों में सुरक्षा का भरोसा भी लौटाया। योगी सरकार में बड़े दंगों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया और आपराधिक घटनाओं में लगातार गिरावट दर्ज की गई। यह बदलाव सामाजिक वातावरण में भी दिखाई देने लगा है। जहां लोग देर रात तक काम और यात्रा करने में पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे हैं, महिलाओं के लिए तो उत्तर प्रदेश अब पूर्ण सुरक्षित हो गया है।

बुनियादी ढांचे में निवेश से विकास को मिली गति

दरअसल, कभी उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य का तमगा मिलने के पीछे कमजोर बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) भी एक बड़ा कारण था। सड़कों की खस्ता हालत, अधूरी परियोजनाएं और कनेक्टिविटी की कमी ने औद्योगिक विकास की राह में रोड़ा अटकने का काम किया था। योगी सरकार ने इस मोर्चे पर आक्रामक रणनीति अपनाई, एक्सप्रेस–वे का जाल बिछाने का जो काम शुरू किया गया, उसने प्रदेश का नक्शा ही बदल दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे, गंगा एक्सप्रेस–वे और आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे जैसी परियोजनाओं ने न केवल आवागमन को सुगम बनाया, वरन औद्योगिक क्लस्टरों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। हवाई अड्डों के विस्तार और नए एयरपोर्ट की योजनाओं ने प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने का काम किया है।

निवेश और औद्योगीकरण से नई पहचान की ओर उत्तर प्रदेश

कानून–व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का सीधा असर निवेश पर पड़ा। योगी सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित किया। रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, डेटा सेंटर, फार्मा और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश प्रस्ताव आए। डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना ने प्रदेश को सामरिक और औद्योगिक दोनों दृष्टि से नई पहचान दी। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा और अलीगढ़ जैसे शहर रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में उभरने लगे हैं, इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े और तकनीकी कौशल को बढ़ावा मिल रहा है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है, पुरानी बीमारू छवि का एक कारण ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाली भी थी। योगी सरकार ने कृषि को लाभकारी बनाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं, फसल बीमा योजनाओं और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर विशेष ध्यान दिया। गन्ना भुगतान में तेजी और किसानों को समय पर पैसा मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ा, इसके साथ ही डेयरी, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने से कृषि आधारित रोजगार के नए अवसर पैदा हुए।

सामाजिक योजनाएं और शासन की नई शैली से आया बदलाव

योगी सरकार के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने पर जोर दिया गया। आवास योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा और लाभार्थियों को सीधे सहायता मिलने लगी। शासन की यह पारदर्शी शैली उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव का वाहक बनी।

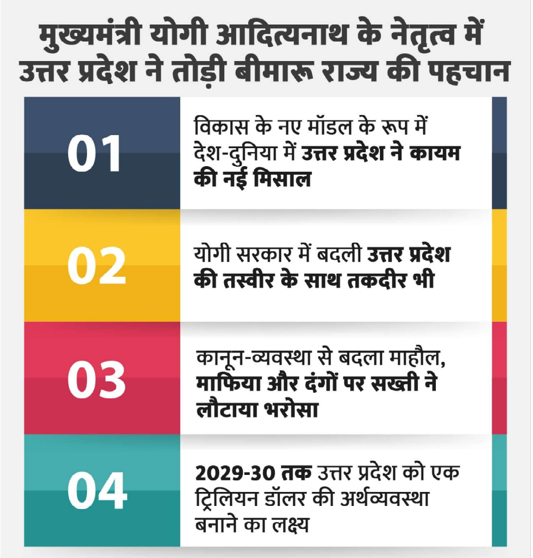

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने तोड़ी बीमारू राज्य की पहचान

01 विकास के नए मॉडल के रूप में देश-दुनिया में **उत्तर प्रदेश ने कायम की नई मिसाल**

02 योगी सरकार में बदली **उत्तर प्रदेश की तस्वीर के साथ तकदीर भी**

03 कानून-व्यवस्था से बदला माहौल, **माफिया और दंगों पर सख्ती ने लौटाया भरोसा**

04 **2029-30 तक** उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

छात्रों ने मतदान करने का लिया शपथ

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर, डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में स्थित मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम सफलता पूर्वक संचालित कराया गया। इस कार्यक्रम में बडी संख्या में छात्र–छात्राओं एवं युवाओं ने भाग लिया। कुलसचिव रीना सिंह एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. ओ.पी. सिंह जी भी उपस्थित रहे । डॉ रीना सिंह जी ने अपने संबोधन में कहा कि मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। एक वोट देश की दिशा और दशा बदल सकता ही। वहीं उपस्थित प्रो० ओ०पी० सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि हर मत की अहमियत है, इसलिए मतदान अवश्य करे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में कार्यक्रम की शुरुआत भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए की गई। इस अवसर पर छात्रों को मतदाता शपथ दिलाई गई, जिसमें सभी ने निष्पक्ष, निर्भिक एवं जिम्मेदार मतदाता बनने का संकल्प लिया। इस अवसर पर एम बी ए डिपार्टमेंट के प्रो विनय चतुर्वेदी जी ने कहा कि युवाओं की भागीदारी से ही लोकतंत्र मजबूत हो सकता है उन्होने ने छात्रो से अपील की कि वे स्वयं मतदान करे और समाज के अन्य लोगो को भी इसके लिए प्रेरित करे । इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में डॉ गजेन्द्र गुप्ता, शैफाली सिहं,आरजू गुप्ता,डॉ वर्षा शुक्ला जी भी उपल्ब्ध रही और अपने वक्तव्यो से छात्रो को मतदान के लिए प्रेरित किया । कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियो का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। यह आयोजन छात्रों में लोकतांत्रिक चेतना और नागरिक जिम्मेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास सिद्ध हुआ ।।

उत्तर प्रदेश के 'राजभवन' का नाम परिवर्तित होकर अब 'जन भवन'

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राज्यपाल के आधिकारिक आवासों के नामकरण के मानकीकरण के संबंध में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम परिवर्तन किया गया है।

पूर्व में 'राज भवन' के नाम से ज्ञात राज्यपाल के आधिकारिक आवास को अब "जन भवन" नाम दिया गया है। उक्त निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का आधिकारिक आवास तत्काल प्रभाव से समस्त शासकीय एवं वैधानिक प्रयोजनों के लिए 'जन भवन' के नाम से अभिहित एवं संबोधित किया जाएगा।

एलडीए की आई0टी0 सिटी योजना 20 फरवरी को होगी लांच

- लैंड पूलिंग नीति के तहत योजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को लॉटरी से आवंटित किये जाएंगे विकसित भूखण्ड
- इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मर्करी हॉल में होगा लॉटरी का आयोजन, 288 से 35 वर्गमीटर क्षेत्रफल के होंगे भूखण्ड

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण की आई0टी0 सिटी योजना 20 फरवरी, 2026 को लांच होगी। इसमें सबसे पहले उन भू–स्वामियों को भूखण्ड आवंटित किये जाएंगे, जिन्होंने लैंड पूलिंग नीति के तहत योजना के लिए अपनी भूमि निःशुल्क दी है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को बैठक करके इस बाबत आदेश जारी कर दिये हैं। प्रथम चरण में 288 से 35 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड लांच किये जा रहे हैं। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सुल्तानपुर रोड पर 3490 एकड़ क्षेत्रफल में आई0टी0 सिटी योजना का विकास किया जा रहा है। जिसके लिए मोहनलालगंज तहसील के ग्राम–बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, मोहारी कला, खुजौली और भटवारा की जमीन ली जा रही है। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुसार लैंड पूलिंग, भूमि अर्जन, आपसी सहमति से क्रय के आधार पर भूमि जुटाव का कार्य किया जा रहा है।

इन 04 सेक्टरों में आवंटित होंगे भूखण्ड

उपाध्यक्ष ने बताया कि 27 जनवरी, 2026 तक जिन भू–स्वामियों के लैंड पूलिंग के एग्रीमेंट निष्पादित होंगे। उन सभी को लॉटरी के माध्यम से योजना में ही निःशुल्क विकसित भूखण्ड आवंटित किये जाएंगे। इसके लिए योजना के सेक्टर–15, 16, 17 एवं 18 में भूखण्ड नियोजित किये जा रहे हैं। आगामी 20 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मर्करी हॉल में भू–स्वामियों की उपस्थिति में लॉटरी ड्रा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 275 भू–स्वामियों ने लैंड पूलिंग नीति के तहत अपनी लगभग 125 एकड़ भूमि का एग्रीमेंट किया है। इसके अलावा 150 एकड़ से अधिक भूमि के अनुबंध के प्रस्ताव प्रक्रिया में हैं।

288 से 35 वर्गमीटर तक के होंगे भूखण्ड

आई0टी0 सिटी योजना अपनी सर्वोत्तम रोड कनेक्टिविटी के कारण लोगों के लिए काफी उपयोगी बनेगी। योजना में 288 वर्गमीटर से 35 वर्गमीटर क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड नियोजित किये जा रहे हैं। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लैंड पूलिंग करने वाले भू–स्वामियों को भूखण्ड आवंटित करने के बाद आम लोगों के लिए भूखण्डों का पंजीकरण खोला जाएगा। भूखण्डों की कीमत लगभग 4,000 रूपये प्रति वर्गफिट प्रस्तावित है।

खुशखबरी : अब अपने गांव में ही मिलेंगी आधार से जुड़ी सेवाएं

राजधानी लखनऊ की दो ग्राम पंचायतों से आधार सेवाओं का शुभारंभ
पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में सेवा विस्तार की योजना
अब तक 800 से अधिक पंचायत सहायकों को दिया जा चुका प्रशिक्षण
सीएम योगी का विजन : पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त कर रहा पंचायतीराज विभाग

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पंचायती राज विभाग ने लखनऊ में ग्राम पंचायत स्तर पर आधार केंद्रों की शुरुआत कर दी है, जिससे ग्रामीणों को आधार से जुड़ी सेवाएं अब अपने गांव में ही उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ब्लॉक सरोजनीनगर की ग्राम पंचायत भटगवां पांडेय तथा चिनहट ब्लॉक की सैरपुर ग्राम पंचायत में आधार सेवाएं सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दी गई हैं। इन दोनों ग्राम पंचायतों में अब तक 40 से अधिक ग्रामीणों को आधार से संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं, जिससे उन्हें अब शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।

चरणबद्ध तरीके से 57,694 ग्राम पंचायतों तक मिलेगी सुविधा

यह पहल पंचायत स्तर पर नागरिक सेवाओं की सहज, पारदर्शी और सुलभ उपलब्धता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। विभाग की योजना के अनुसार, पहले चरण में प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी, जिसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा।

इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत सहायकों का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अब तक 800 से अधिक पंचायत सहायकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि शेष पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण कार्य प्रगति पर है।

ग्रामीणों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि ग्राम स्तर पर आधार सेवाओं की शुरुआत ग्रामीणों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह पहल न केवल समय और संसाधनों की बचत करेगी, बल्कि पंचायतों को आत्मनिर्भर और सक्षम भी बनाएगी।

डिजिटल इंडिया और सशक्त पंचायतों के संकल्प को साकार करने की दिशा में बड़ी शुरुआत

पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने कहा कि विभाग ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आधार सेवाओं की यह शुरुआत पंचायतों को नागरिक सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। आने वाले समय में इसका लाभ प्रदेश के हर गांव तक पहुंचेगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर आधार सेवाओं की यह पहल डिजिटल इंडिया और सशक्त पंचायतों के संकल्प को साकार करने की दिशा में बड़ी शुरुआत मानी जा रही है।

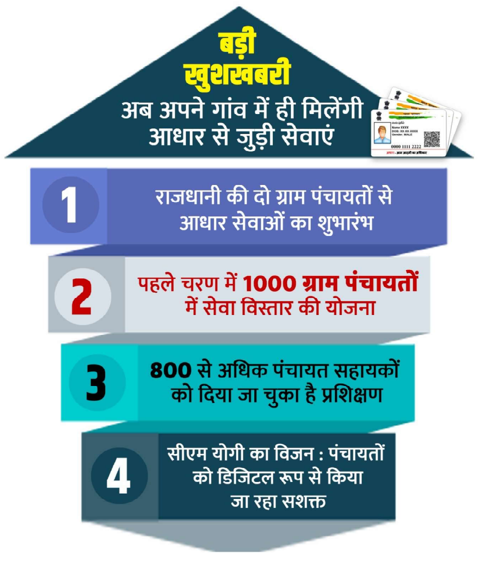

बड़ी खुशखबरी
अब अपने गांव में ही मिलेंगी आधार से जुड़ी सेवाएं

1 राजधानी की दो ग्राम पंचायतों से आधार सेवाओं का शुभारंभ

2 पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में सेवा विस्तार की योजना

3 800 से अधिक पंचायत सहायकों को दिया जा चुका है प्रशिक्षण

4 सीएम योगी का विजन : पंचायतों को डिजिटल रूप से किया जा रहा सशक्त

संक्षिप्त

दबिश देने हाईकोर्ट पहुंच गये दरोगाजी, झूठ बोलकर घुसे अंदर, दारोगा–सिपाही समेत तीन निलंबित

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में काकोरी थाने के दो दरोगा और एक सिपाही अनाधिकृत रूप से हाईकोर्ट में दबिश देने जा पहुंचे। गौ–तस्करी की आरोपी महिला की गिरफ्तारी की कोशिश की। अधिवक्ता के चेंबर में बैठी महिला को साथ ले जाने का प्रयास किया। विरोध पर अधिवक्ताओं से भिड़ गए। अधिवक्ताओं ने उन्हें घेर लिया और पुलिस चौकी के सुपुर्द कर दिया। जांच में पता चला कि तीनों ने प्रवेश का पास भी नहीं बनवाया था। झूठ बोलकर अंदर आए थे। गेट पर एडवोकेट जनरल कार्यालय में जाने की बात बताई और अधिवक्ता के चेंबर में दबिश डाल दी। पुलिस उपायुक्त पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने तीनों को निलंबित कर दिया।अधिवक्ता सज्जाद हुसैन की तहरीर पर दोनों दरोगा व सिपाही के खिलाफ विभूतिखंड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एक मुकदमा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से भी दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर विभूतिखंड अमर सिंह के मुताबिक अधिवक्ता सज्जाद हुसैन और अधिवक्ता आलोक शर्मा के मुताबिक पुलिस कर्मियों में काकोरी थाने के दरोगा उस्मान खान, लाखन सिंह और सिपाही पुष्पेंद्र सिंह है। काकोरी थाने में 14 जनवरी को माल के ऊंचाखेड़ा गांव में रहने वाले सुशील कुमार ने अमीनाबाद निवासी वासिफ के खिलाफ गोवध निवारण अधिनयम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। वासिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वासिफ ने आमिना खातून का नाम भी गो–कसी में बताया ।काकोरी पुलिस आरोपी आमिना की तलाश में दबिश दे रही थी। लोकेशन के आधार पर दरोगा उस्मान खान, लाखन सिंह और सिपाही पुष्पेंद्र समेत अन्य लोग हाईकोर्ट पहुंच गए। पुलिस कर्मियों ने हाईकोर्ट में प्रवेश का पास भी नहीं बनवाया था। तीनों के साथ महिला पुलिसकर्मी भी थी। आमिना की तलाश में पुलिस कर्मी अनाधिकृत रूप से दबिश देने अधिवक्ता गुफरान के चेंबर 515 सी ब्लाक में पहुंच गए। चेंबर में घुसकर आमिना को घेर लिया। जब तक आमिना को पकड़ते तो अधिवक्ताओं ने विरोध किया। इस पर पुलिस कर्मी उनसे अभद्रता करने लगे ।अधिवक्ताओं के विरोध पर मामला हाईकोर्ट के सुरक्षाकर्मी भी पहुंच गए।

देरी से पहुचे संसद तो सांसदों की कटेगी हाजिरी, एक दिन का वेतन भी कटेगा-बिरला

संवाददाता

लखनऊ। संसद के बजट सत्र में लोकसभा सचिवालय सांसदों की हाजिरी को लेकर नई शुरुआत करने जा रहा है। सांसदों की हाजिरी सदन के भीतर सीट पर बैठकर ही डिजिटल तरीके से लग पाएगी। कोई सांसद देरी से सदन में पहुंचता है और तब तक हंगामे या किसी और वजह से सदन दिनभर के लिए स्थगित हो जाता है तो फिर उस दिन की हाजिरी नहीं लग पाएगी। उन्हें एक दिन के वेतन–भत्ते से हाथ धोना पड़ेगा ।लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम यह प्रावधान करने जा रहे हैं कि सदन में पहुंचकर ही हाजिरी लगाई जा सकेगी। अभी तक सदन के बाहर हाजिरी के लिए जो रजिस्टर होता था, अब उसे हटा देंगे। ऐसे सांसद जो रजिस्टर में हाजिरी लगाकर चले जाते थे, या सदन स्थगित होने के बाद पहुंचते थे, उनके लिए मुश्किल होगी। उन्हें सदन में जाना ही होगा। संसद की कार्यवाही डिजिटल हो चुकी है। अब उसमें एआई का इस्तेमाल परीक्षण के तौर पर चल रहा है। इसमें काफी निगरानी और सावधानी की जरूरत है। अभी परीक्षण के तौर पर वक्ताओं के भाषणों के अनुवाद में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बाद में लोग उसे चेक करते हैं। यह 80 फीसदी तक सटीक है ।आईटी कंपनी की मदद से इसे 100 फीसदी सटीक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मानसून सत्र से अनुवाद को पूरी तरह से एआई संचालित कर देंगे। इससे फायदा यह होगा कि अभी अनुवाद के कारण चार घंटे में कार्यवाही का ब्योरा वेबसाइट पर अपलोड होता है ।एआई से आधे घंटे में हो जाएगा। अनुसंधान में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा ।जेल जाने पर मंत्रियों को पद से हटाने के प्रावधान से जुड़े विधेयक पर संसदीय समिति में विपक्ष शामिल नहीं हुआ लेकिन अब विपक्ष की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि वह अपने विचार रखना चाहता है। इस बारे में पूछे जाने पर बिरला ने कहा कि यदि वे आते हैं तो उनके विचारों को समाहित करने का प्रयास किया जाएगा। बजट सत्र पर विपक्ष के संभावित रुख पर बिरला ने कहा कि वे चाहते हैं सदन चले। विपक्ष को अपनी बात चर्चा में रखनी चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में वह हर बात रख सकता है ।ओम बिरला ने कहा कि लखनऊ में चल रहे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कहा, ज्यादातर विधानसभाएं साल में 30 दिन भी नहीं चल पा रही हैं। सम्मेलन में संकल्प पारित करेंगे कि विधानसभाएं न्यूनतम 30 दिन चले। कुछ का रिकॉर्ड अच्छा है ।एक प्रश्न के उत्तर में बिरला ने कहा कि स्पीकरों के अधिकारों पर भी कई बैठकों में चर्चा हुई है। वे चाहते हैं कि स्पीकर के अधिकार असीमित नहीं होने चाहिए ।बिरला ने कहा,संसद के अलावा विधानसभाओं को पेपरलेस बनाया जा चुका है। अनेक विधानसभाओं की कार्यवाही यूट्यूब पर लाइव भी हो रही है।

अखिलेश दिन में सपना देखते हैं, सपा का जंगलराज जनता नहीं भूली : ब्रजेश पाठक

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ/बागपत। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार बनने के अखिलेश यादव के दावे को खारिज करते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि जब–जब प्रदेश में सपा की सरकार बनी, तब–तब गुंडाराज और अराजकता का माहौल रहा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता पाठक ने कहा कि सपा का जंगलराज प्रदेश की जनता आज भी नहीं भूली है। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में सपा की सरकार बनने के यादव के दावे पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शदिन में सपने देखतेश हैं और भाजपा की आलोचना करते रहते हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा, जब–जब प्रदेश में सपा की सरकार बनी, तब–तब गुंडाराज और अराजकता का माहौल रहा। गरीबों की दुकानों, जमीनों और मकानों पर कब्जे किए गए। कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट थी और बहन–बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है और सभी जिलों को समान रूप से बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार में लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। इससे पहले उपमुख्यमंत्री ने बागपत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का औचक निरीक्षण किया, जहां गंभीर अव्यवस्थाएं सामने आईं। निरीक्षण के दौरान सीएचसी परिसर में गंदगी फैली मिली, दीवारों से प्लास्टर उखड़ा हुआ था, कई कक्षों में ताले लगे थे और विद्युत उपकरण खुले में रखे मिले। इन खामियों को देखकर पाठक ने सीएचसी अधीक्षक डॉ. विभाष राजपूत, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. तीरथलाल और जिलाधिकारी अस्मिता लाल पर नाराजगी जताई और व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

नवयुग कन्या महाविद्यालय में डिजिटल टूल्स पर राष्ट्रीय कार्यशाला का भव्य आयोजन

संवाददाता

लखनऊ। नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, लखनऊ के मनोविज्ञान विभाग द्वारा आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के सहयोग से "निमहांस द्वारा विकसित मानसिक कल्याण हेतु डिजिटल टूल्स" विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले डिजिटल टूल्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक कलंक को कम करना तथा समग्र कल्याण को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में जोमी टी. जोस, प्रोग्राम मैनेजर, क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग, निमहांस, बेंगलुरु ने युवाओं द्वारा झेली जाने वाली उन चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जो सामाजिक कलंक, सीमित जागरूकता या सुलभ संसाधनों की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। उन्होंने निमहांस द्वारा विकसित निःशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे "लेट्स टॉक लाइफ फोरम" एवं "माइंड नोट्स" मोबाइल ऐप की जानकारी दी।

छत्तीसगढ़ की धरती जनजातीय शौर्य और बलिदान की साक्षी : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री शहीद शिरोमणि गैंदसिंह के 201वें शहादत दिवस एवं श्रध्दांजलि सभा कार्यक्रम में हुए शामिल

शहीद गैंदसिंह के नाम पर चौक, मूर्ति स्थापना और सामाजिक केंद्रों की घोषणा

बीएनई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज अखिल भारतीय हल्बा–हल्बी आदिवासी समाज के तत्वावधान में साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में आयोजित शहीद शिरोमणि गैंदसिंह के 201वें शहादत दिवस एवं श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने महान जनजातीय नायक एवं स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत शहीद गैंदसिंह का पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने शहीद गैंदसिंह के सम्मान में नया रायपुर में चौक के नामकरण एवं मूर्ति स्थापना, चंगोराभाटा स्थित समाज के सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार, तथा बालोद जिले के देवरी, कांकेर जिले के मरकाटोला, दानीटोला, नगरी, डोंगरगांव एवं बस्तर जिले के भानपुरी तथा करूटोला में हल्बा समाज के सामाजिक केंद्रों के निर्माण हेतु प्रत्येक स्थान के लिए 10–10 लाख रुपये प्रदान किए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही ग्राम कितूर में रंगमंच निर्माण तथा चपका बस्तर में श्रीराम मंदिर के जीर्णोद्धार की भी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनजातीय समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और समृद्ध रहा है। उन्होंने कहा कि देश में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भले ही वर्ष 1857 से मानी जाती है, किंतु उससे बहुत पहले ही छत्तीसगढ़ की धरती पर जनजातीय क्रांतियों की गूंज सुनाई देने लगी थी। महान क्रांतिकारी शहीद गैंदसिंह अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष करते हुए वर्ष 1825 में शहीद हुए, और उस कालखंड में भी आदिवासी समाज ने आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक–दो नहीं बल्कि कुल 14 जनजातीय क्रांतियां हुईं, जिन्होंने अंग्रेजों की सत्ता की नींव हिला दी। यह धरती शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह और वीर गुण्डाधुर जैसे महान जननायकों की भूमि रही है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश इन वीरों और जनजातीय नायकों को लंबे समय तक इतिहास के पन्नों में उचित स्थान नहीं मिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय नायकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हुई 14 जनजातीय क्रांतियों पर आधारित ट्राइबल म्यूजियम नया रायपुर में निर्मित किया गया है, जिसका लोकार्पण स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस संग्रहालय में इन सभी क्रांतियों का सचित्र विवरण एवं गहन जानकारी प्रस्तुत की गई है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि सभी लोग इस म्यूजियम का अवश्य अवलोकन करें, ताकि छत्तीसगढ़ की बलिदानी धरती में जनजातीय नायकों के योगदान को भली–भांति समझा जा सके। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज देश के सर्वोच्च पद पर जनजातीय समाज की बेटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसीन हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश का नेतृत्व भी जनजातीय समाज के बेटे के हाथों में है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए। उनके नेतृत्व में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया गया, जो आज हजारों करोड़ रुपये के बजट के साथ जनजातीय समाज के विकास को नई दिशा दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय ऐतिहासिक है। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना एवं प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय समाज के कल्याण की नई इबारत लिखी जा रही है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता से किया जा रहा है। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारे पुरखों ने शिक्षा को विकास का मूलमंत्र बताया है। शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रगति की है और आज प्रदेश में आईआईएम, आईआईटी और एम्स जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान संचालित हो रहे हैं। उन्होंने समाज के प्रबुद्धजनों से शिक्षा को बढ़ावा देने, शासन की योजनाओं की जानकारी समाज तक पहुंचाने तथा युवाओं को अपने अधिकारों और लक्ष्यों के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अंचल में नक्सलवाद लंबे समय तक विकास में सबसे बड़ी बाधा रहा है, किंतु डबल इंजन सरकार के संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से इस बाधा को दूर किया जा रहा है। वर्षों से विकास से वंचित इस अंचल में अब विकास की नई धारा प्रवाहित हो रही है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि शहीद गैंदसिंह छत्तीसगढ़ के पहले वीर शहीद जननायक थे, जिन्होंने वर्ष 1824–25 में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा संसाधनों की लूट और आदिवासियों के शोषण के खिलाफ साहसिक संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के जनजातीय नायकों का योगदान अतुलनीय रहा है। कार्यक्रम में अखिल भारतीय हल्बा–हल्बी आदिवासी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र माहला, महामंत्री गिरवर सिंह ठाकुर, महेश गागड़ा सहित समाज के अनेक गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ की कला आयरलैंड तक पहुँची : डबलिन में छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की गूंज

छत्तीसगढ़ की कला आयरलैंड तक पहुँचना गौरव का विषय : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

बीएनई

रायपुर। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में भारत की सांस्कृतिक विविधता की एक सशक्त झलक देखने को मिली, जब स्टेट कल्चरल इवेंट सीरीज़ के तहत भारतीय दूतावास, डबलिन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पर केंद्रित भव्य सांस्कृतिक आयोजन का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आयरलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्घाटन आयरलैंड में भारत के राजदूत अखिलेश मिश्रा द्वारा किया गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय परंपराओं और राज्य की विशिष्ट पहचान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे आयोजन भारत की विविधता को वैश्विक मंच पर सशक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं। आयोजन के दौरान छत्तीसगढ़ पर आधारित एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसमें राज्य की कला, संस्कृति, परंपरा और विकास यात्रा को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पारंपरिक हस्तशिल्प की प्रदर्शनी ने आगंतुकों को विशेष रूप से आकर्षित किया, जहाँ राज्य की कारीगरी की बारीकी और सौंदर्य को सराहा गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कड़ी में पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुत लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समां बांध दिया। कलाकारों की जीवंत प्रस्तुतियों ने छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की आत्मा को आयरलैंड की धरती तक पहुँचा दिया और दर्शकों से भरपूर प्रशंसा प्राप्त की। कार्यक्रम का समापन छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों के साथ हुआ, जिसने उपस्थित अतिथियों को राज्य की स्वादिष्ट पाक–परंपरा से परिचित कराया। कुल मिलाकर यह आयोजन छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और पहचान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल साबित हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आयरलैंड की राजधानी डबलिन में आयोजित छत्तीसगढ़ केंद्रित सांस्कृतिक कार्यक्रम ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला, संस्कृति और परंपराओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाई है। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि प्रदेश की लोकसंस्कृति अब वैश्विक दर्शकों तक पहुँच रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्टेट कल्चरल इवेंट सीरीज़ के अंतर्गत भारतीय दूतावास, डबलिन द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम भारत की सांस्कृतिक विविधता और "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की भावना को सशक्त रूप से प्रस्तुत करता है। उन्होंने इस आयोजन के लिए भारतीय दूतावास और आयरलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय की सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला, हस्तशिल्प और लोक परंपराएँ राज्य की पहचान का मूल आधार हैं। आयरलैंड में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ की हस्तकला, पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों ने सराहा, यह राज्य के कलाकारों और कारीगरों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों से पर्यटन, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को भी वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएँ मिलती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की कला–संस्कृति के संरक्षण और प्रचार–प्रसार के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को देश–विदेश में इसी तरह मंच मिलेगा और राज्य की विशिष्ट पहचान विश्व पटल पर और अधिक सुदृढ़ होगी।

EMBASSY OF INDIA IN DUBLIN
STATE CULTURAL EVENT SERIES
CHHATTISGARH
CHHATTISGARH

लेखपाल बेटे से परेशान माँ बाप ने मांगी इच्छा मृत्यु

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। कलक्ट्रेट पहुंचे बुजुर्ग दम्पति इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए फफक कर रो पड़े। हाथ में इच्छा मृत्यु लिखी हुई पट्टिका पकड़ वह डीएम ऑफिस पहुंचे और अपने लेखपाल बेटे पर ही हत्या की साजिश रचने के गम्भीर आरोप लगा दिए। डीएम ने मामले की जांच कराने का भरोसा दिया है। बुजुर्ग दम्पति बाबूराम और उनकी पत्नी कमलेश कुमारी इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के भूड़पुरवा गांव के रहने वाले हैं। वह अपने छोटे बेटे देवेंद्र से परेशान हैं जोकि सिदार्थनगर जिले की इटवा तहसील में लेखपाल की पोस्ट पर तैनात है। बाबूराम और उनकी पत्नी कमलेश कुमारी ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को शिकायती पत्र सौंपा। जिसमें उन्होंने बताया कि छोटा बेटा देवेंद्र लेखपाल है और बड़े बेटे अनिल की पत्नी सरकारी टीचर है। जबकि मझिला बेटा शिवानंद आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसके बावजूद खेती में मेरा साथ देकर उसने अपने दोनों भाइयों अनिल और देवेंद्र को पढ़ाने में सहयोग किया। सीपीएमटी, मेडिकल प्रवेश परीक्षा और पीसीएस की तैयारियों के लिए तमाम कोचिंग में पैसा खर्च किया। ऐसे में जब शिवानन्द को दो एकड़ जमीन दान में दे दी तो देवेंद्र बौखला गया और अपने साले व ससुर की मदद से हम पति–पत्नी व मझले बेटे शिवानन्द की हत्या कराना चाहता है। वह लोग 15 जून 2025 को भी घर में घुसकर हमला कर चुके हैं। शिकायत करने पर पुलिस भी कोई कार्यवाही नहीं करती। ऐसे में मर जाना ही बेहतर हैं। इसलिए इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की जाए।

इच्छा मृत्यु के सम्बन्ध में
महोदय जिलाधिकारी

पिता बाबूराम ने रोते हुए बताया कि वर्ष 2001 में देवेंद्र का नवोदय में दाखिला होना था, लेकिन प्रिंसिपल ने एडमिशन लेने से मना कर दिया। जिसके बाद वह इलाहाबाद हाईकोर्ट तक गए और एक साल केस लड़ा। इसके लिए 60 हजार रुपया लोन लिया था, जोकि अब ब्याज समेत 3 लाख हो गया है। बाबूराम ने बताया कि देवेंद्र ने 26 जनवरी 2023 में खुद की मर्जी से उमा नाम की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था। कुछ समय बाद उमा ने सुसाइड कर लिया। ऐसे में देवेंद्र के सामने तमाम समस्याएं आ गईं। उसे झंझटों से बचाने के लिए भाई शिवानन्द ने देवेंद्र को 8 लाख रुपए की मदद की थी। इसके बाद देवेंद्र ने 6 जून 2025 को फिर परिजनों की सहमति के बिना शादी कर ली। अब उसके ससुर, साले और पत्नी मकान व खेती हड़पना चाहते हैं।

मेघालय को जियोस्पेशियल तकनीक, डिजिटल गवर्नेंस और जनसेवा के लिए तीन राष्ट्रीय पुरस्कार

शहरी विकास, नागरिक सेवाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिला राष्ट्रीय सम्मान, 6वें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समिट एवं अवॉर्ड्स में

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित 6वें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समिट एवं अवॉर्ड्स में मेघालय राज्य को जियोस्पेशियल तकनीक, जनसेवा और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए तीन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा के नेतृत्व में राज्य द्वारा शुरू की गई नई और टेक्नोलॉजी–आधारित पहलों को मान्यता देते हैं। शहरी विकास और आधारभूत ढांचे की योजना, नागरिक सेवाओं की डिलीवरी और स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक के प्रभावी उपयोग के माध्यम से मेघालय ने समावेशी और डेटा–आधारित शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर साबित किया है। योजना, निवेश प्रोत्साहन एवं सतत विकास विभाग के अंतर्गत मेघालय ONE को "डिजिटल तकनीक के अभिनव उपयोग के माध्यम से जनसेवा में सुधार" श्रेणी में पुरस्कार मिला। मेघालय ONE एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए नागरिक सरकारी योजनाओं की जानकारी, सेवाओं का लाभ और शिकायतो का निवारण एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। यह सुविधा वेब, भौतिक सेवा केंद्रों और गांवों में तैनात डेटा वॉलंटियर्स (Village Data Volunteers) के माध्यम से उपलब्ध है। मेघालय स्टेट GIS और UAV सेंटर, जो कि मेघालय बेसिन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MBDA) और योजना, निवेश प्रोत्साहन एवं सतत विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत है, को "परिवहन, शहरी विकास और अन्य परियोजनाओं में जियोस्पेशियल तकनीक के उत्कृष्ट उपयोग" की श्रेणी में सम्मानित किया गया। इस पहल को इसके प्रमुख प्लेटफॉर्म मेघालय स्टेट जियो पोर्टल (मेघालय स्टेट जियोहब) के लिए अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। एआई–संचालित एनालिटिक्स के जरिए यह प्लेटफॉर्म निर्णय लेने में सहायक महत्वपूर्ण जानकारी देता है और रियल–टाइम डेटा के माध्यम से वनों की कटाई, मौसम पूर्वानुमान और जल प्रबंधन जैसे रुझानों को ट्रैक करने में मदद करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), स्वास्थ्य विभाग, मेघालय सरकार को "अभिनव डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा एनालिटिक्स" श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ। NHM को इसके डिजिटल पहल MOTHER ऐप के लिए अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाज़ा गया। वर्ष 2020 से 2025 के बीच, मेघालय में मातृ मृत्यु दर में लगभग 60 प्रतिशत और शिशु मृत्यु दर (IMR) में 34 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। यह दिखाता है कि रियल–टाइम डेटा किस तरह स्वास्थ्य प्रणाली में समय पर समाधान और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन Governance Now द्वारा किया गया, जो सार्वजनिक नीति और शासन पर केंद्रित एक प्रमुख प्रकाशन है।

DIGITAL TRANSFORMATION SUMMIT & AWARDS
Enabling India's Next Leap Through Digital Governance
16th JANUARY 2026
NEW DELHI

भदोही में प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद पर प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान

यह स्थिति हिंदुओं के लिए दु:खद, शंकराचार्य और योगी मिलकर विवाद सुलझाएं

हिंदू मंगलवार और शनिवार को मंदिरों में करें सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ

बीएनई

भदोही। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने बुधवार को भदोही में प्रयागराज माघ मेला में शंकराचार्य विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और महंत योगी आदित्यनाथ को सुझाव नहीं दे सकता, लेकिन प्रार्थना करता हूं कि मामला शांत करें। हिंदुओं के लिए यह पीड़ादायी स्थिति है। हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि प्रयागराज मामले पर मैं हूं बेहद दुखी हूँ, लेकिन हिंदू बंटेगा तो कटेगा। कहा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और महंत योगी आदित्यनाथ को सुझाव नहीं दे सकता, लेकिन प्रार्थना करता हूं कि मामला शांत करें। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए दोनों पूजनीय संत मिलकर मामला करें शांत। उम्मीद जताया कि दोनों संत मिलकर हिंदू एकता और सम्मान का रास्ता स्वयं ढूंढेंगे। भदोही नगर में बुधवार को प्रवीण तोगड़िया पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अशोक जायसवाल के कार्यालय पर पहुँचे जहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान हिंदू चेतना, एकता और संगठन का विराट संदेश देखने को मिला। नगर के प्रबुद्ध नागरिकों एवं हिंदू समाज के गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि संगठित, जागरूक और संस्कारित हिंदू समाज ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस दिन हिंदू समाज पूर्ण रूप से एकजुट हो जाएगा, उस दिन विश्व पटल पर हिंदू गौरव का परचम लहराएगा। हिंदू समाज को जागृत और संगठित करने के उद्देश्य से उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक हिंदू हर मंगलवार और शनिवार को मंदिरों में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करे, जिससे समाज में आध्यात्मिक शक्ति, एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना और अधिक सशक्त हो। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को हिंदू को जागो, हिंदू को जगाओ का सामूहिक संकल्प भी दिलाया। डॉ. तोगड़िया के विचारों से प्रभावित उपस्थित जनसमूह ने करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया। पूरा परिसर जय श्रीराम और हिंदू एकता जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा, जिससे वातावरण पूर्णतः राष्ट्रभक्ति और उत्साह से भर गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से तरुण शुक्ला, अशोक जायसवाल (पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष), प्रिंस गुप्ता (पूर्व नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी भदोही), दिलीप गुप्ता, राकेश गुप्ता, विनय उमर वैश्य, कामता चौरसिया, लवकुश दुबे, प्रदीप विश्वकर्मा, दीपू, सौरभ चौरसिया, कमलेश जायसवाल, अजय दुबे, अरविंद मौर्य, प्रदीप यादव, अशोक पाल, रिंकू जायसवाल, उमेश सिंह, राजू मोदनवाल, लोकेश सिंह, राजकुमार गुप्ता, नरसिंह यादव, संतोष मोदनवाल, विवेक यादव, विपिन तिवारी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव सहित सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग उपस्थित रहे।

कोल इंडिया की हाई पावर कमेटी का दो दिवसीय एनसीएल दौरा सम्पन्न

बीना, अमलोरी एवं निगाही परियोजनाओं का किया निरीक्षण

संविदाकर्मियों के वेतन, सामाजिक सुरक्षा एवं कार्य-परिस्थितियों की हुई समीक्षा

बीएनई

सिंगरौली। संविदाकर्मियों के वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के उद्देश्य से गठित कोल इंडिया की हाई पावर कमेटी ने एनसीएल की बीना, अमलोरी एवं निगाही परियोजनाओं का दौरा किया। इस दौरान समिति के सदस्यों में केशव राव, निदेशक (मानव संसाधन) – एमएससीएल, मनीष कुमार, निदेशक (मानव संसाधन)–एनसीएल, मु.अंजार आलम, निदेशक (वित्त), ईसीएल, सी.एस. तिवारी, निदेशक (तकनीकी), सीसीएल, गौतम बनर्जी, कार्यकारी निदेशक (एचआर), सीआईएल, जयब्रत मजूमदार, महाप्रबंधक (सीएमसी), सीआईएल, रंजन बेहरा (बीएमएस), शिवकांत पांडे (एचएमएस), नरेश मंडल (एटक), मानस चटर्जी (सीटू) उपस्थित रहे। साथ ही इस अवसर पर महाप्रबंधक (अमलोरी क्षेत्र) आलोक कुमार, महाप्रबंधक (बीना क्षेत्र) आर के सिंह, महाप्रबंधक (निगाही क्षेत्र) राजेंद्र वर्मा, महाप्रबंधक (मानव संसाधन) समीर बरला, उपमहाप्रबंधक(मानव संसाधन) राजेश चौधरी, अमलोरी, बीना व निगाही परियोजनाओं के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। हाई पावर कमेटी ने मंगलवार को बीना व अमलोरी परियोजना का दौरा किया व बुधवार को निगाही परियोजना का दौरा किया। इस अवसर पर खदानो का निरीक्षण किया साथ ही संविदा श्रमिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं जैसे कैंप, रेस्ट शेल्टर, कैंटीन आदि का जायजा लिया गया। सदस्यों ने संविदा कर्मियों से संबंधित वेतन भुगतान, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, स्वास्थ्य व अन्य लाभों की विस्तार से समीक्षा की। समिति ने संविदा श्रमिक शिविरों में विभिन्न वैधानिक दस्तावेजों की जांच भी की व एनसीएल की कार्यसंस्कृति व संविदा कर्मियों को दी जाने वाली सुविधाओं की सराहना की। समिति के सदस्यों ने परियोजना में अधिभार हटाव में कार्यरत संविदा श्रमिकों से संवाद कर उनकी कार्य–परिस्थितियों, सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े मुद्दों पर फीडबैक लिया। इस अवसर पर बीना परियोजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रमिकों को सम्मानित भी किया गया। समिति के सदस्यों ने निगाही में ड्रैगलाइन संचालन व सतत खनन पहल के तहत विकसित बरेजा ईको–पार्क भी देखा । गौरतलब है कि यह संयुक्त समिति एनसीएल के दो दिवसीय दौरे थी जो संविदा श्रमिकों के जीवन स्तर, कार्य–परिस्थितियों एवं सामाजिक सुरक्षा के उन्नयन हेतु समग्र मूल्यांकन कर अपने सुझाव देती है, जिससे भविष्य में संविदाकर्मियों के हित में और अधिक प्रभावी नीतिगत सुधार सुनिश्चित किए जा सकें।

अगले पांच सालों में बदलेगी भारत की तस्वीर, बोले वैष्णव– भारतीय अर्थव्यवस्था हर साल हासिल करेगी नई ऊंचाई

एजेंसी, दावोस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि मुद्रास्फीति में नरमी और मजबूत आर्थिक वृद्धि के बल पर भारतीय अर्थव्यवस्था अगले पांच वर्षों में वास्तविक रूप से छह–आठ प्रतिशत और मौजूदा कीमतों पर 10–13 प्रतिशत की दर से बढ़ती रहेगी। वैष्णव ने यहां विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के इतर आयोजित बेट ऑन इंडिया बैंक ऑन द फ्यूचर सत्र को संबोधित करते हुए अनुमति प्रक्रियाओं के सरलीकरण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूरसंचार टावर स्थापित करने में लगने वाला औसत समय 270 दिनों से घटकर सात दिन रह गया है और 89 प्रतिशत अनुमतियां अब तुरंत मिल रही हैं। वैष्णव ने नीति के उद्देश्य और जमीनी क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि राजनीतिक नेतृत्व के रूप में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि नौकरशाही राजनीतिक निर्णयों के अनुरूप काम करे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743